

प्रेषक,

पी०सी०शर्मा,
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

समरत जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग

देहरादून: दिनांक: २। फरवरी 2005

विषय: उत्तरांचल राज्य में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का लाइसेंस के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों तथा संघ राज्यों के मंत्रिगणों द्वारा निर्णय लिया गया है कि सस्ते गल्ले की दुकानों का लाइसेंस उनके वारिसों को वरीयता के आधार पर आवंटित किया जाए।

2. इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना है कि वारिसों का तात्पर्य उस दशा से है:-
 1. जहाँ सरकारी सस्ता गल्ले विक्रेता की इस अवधि में मृत्यु हो गयी हो।
 2. सरकारी सस्ता गल्ले विक्रेता के विरुद्ध न्यायालय में कोई शिकायत लम्बित/विचाराधीन न हो।
 3. सरकारी सस्ते गल्ले विक्रेता के आश्रित के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद लम्बित न हो।
 4. सरकारी सस्ते गल्ले विक्रेता के वारिसों में वारिस का कोई विवाद न हो।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण लम्बित हो तो नियमानुसार उसे वारिस का लाभ प्रदान किया जाये।
4. उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा पूर्व में जारी वारिस के संबंध में शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

(पी०सी०शर्मा)

सचिव।

संख्या- 280 (1)/XIX/ 2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अशा०प०स०- ६(७) / २००४, पी०डी०। (पी०टी०- ।।।), दिनांक: ०३.१२.२००४ के कम में।

.....2/-

2. आयुक्त, कुमायू/गढ़वाल, उत्तरांचल।
3. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
4. संभागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायू/गढ़वाल संभाग, उत्तरांचल।
5. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तरांचल।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

०९
(एम०सी०सप्रेती)
अपर सचिव।